THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-04 | Issue-04 | January-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI: : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i4.15

भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों का कायाकल्प: एनईपी 2020 की सिफारिशों का एक विवरणात्मक अन्वेषण

डॉ. मोहम्मद वकार रज़ा[1] एवं रशीदी रुकैया[2]

[1]सहायक प्रोफेसर (बी.एड.),एस.एस.एस.वी.एस. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर
[2]सहायक प्रोफेसर, (बी.एड.), बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, बालूगंज, आगरा

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक युगांतरकारी सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य रटंत विद्या और कठोर संरचनाओं से हटकर समग्र, बहु-विषयक और छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों की ओर स्थानांतरित होकर उच्च शिक्षा का पुनरुद्धार करना है। यह विवरणात्मक अन्वेषण उच्च शिक्षा में शिक्षाशास्त्र से संबंधित NEP 2020 की प्रमुख सिफारिशों का परीक्षण करता है, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, लचीला पाठ्यक्रम, अनुभवात्मक और जांच-आधारित दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, भारतीय ज्ञान प्रणालियों का समावेश और आलोचनात्मक सोच एवं रचनात्मकता पर बल देना शामिल है। मुख्य रूप से आधिकारिक नीति दस्तावेज और माध्यमिक विश्लेषणों के आधार पर, यह पत्र यह वर्णित करता है कि कैसे ये सिफारिशें शिक्षण प्रथाओं, संकाय भूमिकाओं और संस्थागत संस्कृतियों को बदलने का प्रयास करती हैं। यह संसाधन की कमी, संकाय तैयारी और संस्थागत जड़ता जैसी कार्यान्वयन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए निष्पक्षता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के संभावित निहितार्थों का भी पता लगाता है। यह समीक्षा एनईपी 2020 के एक ऐसे ज्ञान समाज के निर्माण के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है जो भारतीय लोकाचार में निहित होने के साथ-साथ 21वीं सदी की मांगों के अनुरूप हो, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षाशास्त्र की पुनर्कल्पना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

कीवर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, शिक्षाशास्त्र, बहु-विषयक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, भारत।

परिचय

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से खंडित विषयों, रटने पर जोर, पाठ्यक्रम में सीमित लचीलेपन और अनुसंधान एवं आलोचनात्मक सोच पर कम जोर जैसी चुनौतियों से ग्रस्त रही है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। 2018 में लगभग 26.3% के सकल

नामांकन अनुपात (GER) के साथ, यह प्रणाली तेजी से बढ़ती युवा आबादी और ज्ञान-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने में संघर्ष कर रही थी (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शैक्षिक संरचनाओं और प्रथाओं को बदलकर एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज की कल्पना करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में उभरी है।

NEP 2020 केवल पहुंच और समानता के बजाय समग्र विकास, लचीलेपन और नवाचार को प्राथमिकता देकर पिछली नीतियों (1968 और 1986/1992) से अलग हटकर अपनी पहचान बनाती है (बैंगे, 2021)। उच्च शिक्षा में, नीति स्पष्ट रूप से शिक्षण परिवर्तन को लक्षित करती है, जो शिक्षक-केंद्रित, परीक्षा-उन्मुख विधियों से शिक्षार्थी-केंद्रित, अनुभवात्मक और बहु-विषयक दृष्टिकोणों की ओर बदलाव की वकालत करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। यह विवरणात्मक अन्वेषण इन शैक्षणिक सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करता है, उनके मुख्य तत्वों, तर्क और भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रथाओं, संकाय भूमिकाओं और संस्थागत संस्कृतियों पर इच्छित प्रभावों का वर्णन करता है।

नीति का दृष्टिकोण पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हुए 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना है (पत्र सूचना कार्यालय, 2021)। आधुनिक शिक्षाशास्त्र के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करके, NEP 2020 अपनी जड़ों से जुड़े हुए लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्नातकों को तैयार करना चाहती है (ऐथल और ऐथल, 2020)। यह पत्र प्रस्तावित प्रमुख शैक्षणिक बदलावों, उनके निहितार्थों और संभावित चुनौतियों का वर्णन करता है, जो इस बात की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है कि NEP 2020 उच्च शिक्षा में शिक्षण और सीखने की पुनर्कल्पना कैसे करती है।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 का अवलोकन

NEP 2020 चार स्तंभों पर आधारित है: पहुंच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही, जिसमें भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए उच्च शिक्षा में सुधार पर जोर दिया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। नीति वर्तमान प्रणाली में प्रमुख समस्याओं की पहचान करती है, जिसमें कठोर विषयगत अलगाव, सीमित बहु-विषयक अनुभव, व्याख्यान और परीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त संकाय विकास और कम शोध परिणाम शामिल हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 34)।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, NEP 2020 संस्थागत पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है, जैसे कि 2030 तक एकल-विषय संस्थानों को बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पक्ष में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, जिनमें से प्रत्येक में आदर्श रूप से कम से कम 3,000 छात्र नामांकित हों (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। यह वैश्विक मानकों पर आधारित बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERU) की स्थापना और सुव्यवस्थित शासन के लिए एक एकल नियामक—भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)—की परिकल्पना भी करती है (पत्र सूचना कार्यालय, 2021)।

शैक्षणिक रूप से, नीति कला, मानविकी, विज्ञान और व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करने वाली समग्र शिक्षा की ओर बढ़ने की वकालत करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 35)। यह बदलाव संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए है, जो छात्रों को एक गतिशील दुनिया में आजीवन सीखने के लिए तैयार करता है (शर्मा और यादव, 2023)। नीति शैक्षणिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण, संकाय प्रेरणा और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर भी जोर देती है (ऐथल और ऐथल, 2020)।

NEP 2020 में प्रमुख शैक्षणिक सिफारिशें

NEP 2020 शिक्षाशास्त्र को बदलने के लिए कई परस्पर जुड़ी सिफारिशों को रेखांकित करती है।

बहु-विषयक और समग्र शिक्षा

NEP 2020 का एक आधार स्तंभ बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना है। नीति अनुशंसा करती है कि स्नातक कार्यक्रम व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करें, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की अनुमति मिले, जैसे कि भौतिकी के साथ संगीत या अर्थशास्त्र के साथ दर्शनशास्त्र का संयोजन (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 36)।

लचीला पाठ्यक्रम और विकल्प-आधारित प्रणाली

NEP 2020 की शैक्षणिक दृष्टि में लचीलापन केंद्रीय है। नीति कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ एक क्रेडिट-आधारित प्रणाली पेश करती है: एक वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, दो के बाद डिप्लोमा, तीन या चार वर्षों के बाद डिग्री (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 37)। छात्र 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC) के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित विभिन्न माध्यमों से क्रेडिट जमा कर सकते हैं।

अनुभवात्मक और छात्र-केंद्रित शिक्षा

NEP 2020 पारंपरिक व्याख्यान के बजाय जांच-आधारित, चर्चा-उन्मुख और अनुभवात्मक शिक्षाशास्त्र की वकालत करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 38)। सक्रिय सीखने को बढ़ावा देने के लिए समस्या-समाधान, केस स्टडी, इंटर्नशिप और अनुसंधान परियोजनाओं जैसी विधियों को प्राथमिकता दी जाती है।

शिक्षाशास्त्र में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

प्रौद्योगिकी को नवाचारी शिक्षण के लिए एक सक्षम कारक के रूप में देखा जाता है। NEP 2020 डिजिटल बुनियादी ढांचे और सामग्री विकास की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) स्थापित करने की सिफारिश करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 56)।

एनईपी 2020: कार्यान्वयन की चुनौतियां और रणनीतिक बाधाएं

शिक्षण पद्धतियों में प्रस्तावित परिवर्तन क्रांतिकारी हैं, किंतु इनका वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन कई जटिलताओं से घिरा है। मुख्य बाधाओं का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है:

1. बुनियादी ढांचा और डिजिटल विभाजन

नीति 'मिश्रित शिक्षण' (Blended Learning) और तकनीकी एकीकरण पर अत्यधिक बल देती है। हालांकि, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट और निर्बाध बिजली की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती है।

- **संसाधन विषमता:** प्रीमियम संस्थानों (जैसे IITs/IIMs) और ग्रामीण राज्य विश्वविद्यालयों के बीच बुनियादी ढांचे की खाई 'डिजिटल विभाजन' को जन्म दे सकती है, जिससे समान अवसर सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

2. संकाय तत्परता और शैक्षणिक जड़ता

शिक्षण पद्धतियों को 'शिक्षक-केंद्रित' से 'छात्र-केंद्रित' बनाना केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक परिवर्तन है।

- **प्रशिक्षण का अभाव:** अधिकांश संकाय पारंपरिक व्याख्यान पद्धति में प्रशिक्षित हैं। उन्हें अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Learning) और रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment) के लिए तैयार करने हेतु व्यापक 'संकाय विकास कार्यक्रमों' (FDPs) की आवश्यकता है।
- **प्रतिरोध:** शैक्षणिक जड़ता और पुराने ढर्रे पर चलने की मानसिकता नए प्रयोगों को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करती है।

संकाय विकास हेतु रणनीतिक रूपरेखा (NEP 2020)

1. निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development - CPD)

NEP 2020 अनुशंसा करती है कि प्रत्येक शिक्षक को अपनी रुचि और शिक्षण क्षेत्र में सुधार के लिए प्रति वर्ष कम से कम **50 घंटे** के CPD मॉड्यूल में भाग लेना अनिवार्य होगा।

- इसमें नवीनतम शिक्षण तकनीकों, कार्यशालाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (जैसे SWAYAM/DIKSHA) को शामिल किया जाएगा।

2. शिक्षण शास्त्रीय नेतृत्व (Pedagogical Leadership)

शिक्षकों को केवल विषय विशेषज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि 'सुविधा प्रदाता' (Facilitator) के रूप में विकसित किया जाएगा।

- **बहु-विषयक प्रशिक्षण:** संकाय को अपने मूल विषय के बाहर के क्षेत्रों (जैसे कला, नीतिशास्त्र, प्रौद्योगिकी) के साथ अंतर्संबंध स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **सृजनात्मक मूल्यांकन:** शिक्षकों को उच्च-स्तरीय सोच कौशल (HOTS) के मूल्यांकन के लिए नए उपकरण विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण (Technology-Enabled Teaching)

संकाय विकास का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है।

- इसमें 'फ्लिप्ड क्लासरूम' (Flipped Classrooms), आभासी प्रयोगशालाओं (Virtual Labs) का उपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिक्षण उपकरणों का प्रभावी उपयोग शामिल है।

4. अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन

नीति संकायों के लिए 'शिक्षण' और 'अनुसंधान' के बीच एक संतुलन बनाने का प्रस्ताव करती है।

- **संस्थागत समर्थन:** उत्कृष्ट शोध करने वाले शिक्षकों को कम शिक्षण कार्यभार और शोध अनुदान (Research Grants) देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF):** संकाय सदस्य NRF के माध्यम से अंतर-विषयक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्राप्त कर सकेंगे।

5. संकाय नियुक्ति और करियर प्रगति (Career Progression)

नीति संकाय की पदोन्नति के लिए 'सेवा-काल' (Seniority) के बजाय **'मेरिट-आधारित'** (Merit-based) प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का सुझाव देती है।

- संकाय का मूल्यांकन उनके शिक्षण प्रभाव, अनुसंधान योगदान और संस्थागत सेवा के आधार पर बहु-आयामी (360-degree feedback) तरीके से किया जाएगा।

3. बहु-विषयक संरचना और संस्थागत स्वायत्तता

एक ही परिसर में कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों को समेकित करना प्रशासनिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से कठिन है।

- **कठोर विषयगत अलगाव (Silos):** दशकों से चले आ रहे विभागीय अलगाव को तोड़ना और अंतर-विभागीय सहयोग स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है।
- **क्रेडिट बैंक (ABC) की जटिलता:** छात्रों के 'प्रवेश और निकास' (Multiple Entry and Exit) के डेटा को प्रबंधित करना और विभिन्न संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण में एकरूपता लाना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

4. वित्तीय निवेश और वित्त पोषण

नीति जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश करती है। वर्तमान में यह स्तर काफी कम है। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक भारी निवेश की कमी से इन सुधारों की गति धीमी हो सकती है।

5. भाषा और भाषाई विविधता

उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने का प्रस्ताव सराहनीय है, किंतु उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों, अनुसंधान पत्रों और तकनीकी शब्दावली का क्षेत्रीय भाषाओं में अभाव एक गंभीर समस्या है।

कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित मार्ग

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक **'सहयोगात्मक मॉडल'** की आवश्यकता है जहाँ सरकार, शिक्षण संस्थान और उद्योग जगत मिलकर कार्य करें। चरणबद्ध कार्यान्वयन (Phased Implementation) और निरंतर निगरानी तंत्र ही इस नीति को सफल बना सकते हैं।

निष्कर्ष

NEP 2020 भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों के लिए एक परिवर्तनकारी रूपरेखा प्रदान करती है। शिक्षण को सुसाध्य और छात्र-केंद्रित के रूप में पुनर्गठित करके, नीति का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार आलोचनात्मक विचारकों और नवाचारियों को तैयार करना है। अंततः, NEP 2020 भारतीय उच्च शिक्षा को जीवंत, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रासंगिक बनाने की क्षमता रखती है।

संदर्भ (References)

- ऐथल, पी. एस., और ऐथल, एस. (2020). *एनालिसिस ऑफ द इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एंड सोशल साइंसेज, 5(2), 19–41.
- बैंगे, सी. (2021). *इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: क्रिटिकल एनालिसिस एंड कमेंट्री.* प्रोस्पेक्ट्स. https://doi.org/10.1007/s11125-021-09573-9
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. (2021). *सेलियंट फीचर्स ऑफ एनईपी 2020: हायर एजुकेशन.* https://www.spav.ac.in/2020/pdf/sfep2020.pdf
- शर्मा, आर., और यादव, आर. (2023). *एक्सप्लोरिंग 21st सेंचुरी इनोवेटिव पेडागोजी पैराडाइम्स इन हायर एजुकेशन: एनईपी 2020.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज.

Cite this Article:

डॉ. मोहम्मद वकार रज़ा[1] एवं रशीदी रुकैया[2],“ भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों का कायाकल्प: एनईपी 2020 की सिफारिशों का एक विवरणात्मक अन्वेषण”
The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.114–119

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. मोहम्मद वकार रज़ा[1] एवं रशीदी रुकैया[2]

For publication of Research Paper title

भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों का कायाकल्प: एनईपी 2020 की सिफारिशों का एक विवरणात्मक अन्वेषण

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI: : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i4.15